



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 302]
No. 302]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 1984/आषाढ़ 7, 1906
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 1984

अदेश

कां०आ० 473(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/84 :- केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कां०आ० 319(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/2/76 तारीख 27 अप्रैल, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैरुव प्लाईवोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाम्पोर, जम्मू कश्मीर नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 26 अप्रैल, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण करने के लिये जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्राधिकृत किया था;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे 30 जून, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित

है, और अवधि के लिये ऐसे बने रहने के लिये सम्य-समय पर निर्देश जारी किये थे [द्विगुण भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कां० आ० 318(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/81, तारीख 25 अप्रैल, 1981, सं० कां०आ० 287(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/82, तारीख 26 अप्रैल, 1982, सं० कां० आ० 763 (अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/82, तारीख 25 अक्तूबर, 1982, सं० कां०आ० 233(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 28 मार्च, 1983, सं० कां०आ० 695(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 29 सितम्बर, 198 और सं० कां०आ० 227(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/1 तारीख 30 मार्च, 1984।]

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय यह है कि लो में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 30 सितम्बर, तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और के लिये प्रभावी बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और वि अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा की उपधारा (2) के परन्तुक के सथ पठित धा को उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 30 सितम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 2(6)/81-सो०यू०ए०सं०]

ए०पी० सरस्वत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department Of Industrial Development)

New Delhi, the 28th June, 1984

ORDER

No. S.O. 473(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 319(E)|18AA|IDRA|76, dated the 27th April, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Jammu & Kashmir Industries Limited to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Plyboard Industries Limited, Pampore, Jammu and Kashmir, for a period of five years, that is, upto and inclusive of the 26th April, 1981;

And, whereas, the Central Government being of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect after the

expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984 [vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 318(E)|18AA|IDRA|81, dated the 25th April, 1981, S.O. 287(E)|18AA|IDRA|82, dated the 26th April, 1982, S.O. 763(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th October, 1982, S.O. 233(E)|18AA|IDRA|83, dated the 28th March, 1983, S.O. 695(E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th September, 1983 and S.O. 227(E)|18AA|IDRA|84, dated the 30th March, 1984.]

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1984.

[F. No. 2(6)81-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.